अध्यक्ष महोदय : आर्डर, आर्डर । दूसरा सवाल पूछने की इजाजत नहीं है ।

12.25 hrs.

PAPERS LAID ON THE TABLE

INDIAN TELEGRAPH (EIGHTH AMENDMENT) RULES

The Minister of Transport and Communications (Shri Jagjivan Ram): I beg to lay on the Table a copy of the Indian Telegraph (Eighth Amendment) Rules, 1962 published in Notification No. S.O. 2158 dated the 14th July, 1962, under sub-section (5) of section 7 of the Indian Telegraph Act, 1885. [*Placed in Library, see No.* LT-328/62]

REPORT OF SCHOOL HEALTH COMMITTEE

The Deputy Minister in the Ministry of Health (Dr. D. S. Raju): On behalf of Dr. Sushila Nayar, I beg to lay on the Table a copy of Report of the School Health Committee (Part I). [*Placed in Library, See* No. LT-320/62.]

12.26 hrs.

COMMITTEE ON PRIVATE MEMBERS' BILLS AND RESOLUTIONS

FIFTH REPORT

Shri Krishnamoorthy Rao (Shimoga): I beg to present the Fifth Report of the Committee on Private Members' Bills and Resolutions.

12.26¼ hrs.

BUSINESS ADVISORY COMMITTEE

FOURTH REPORT

Shri Rane (Buldana): I beg to move:

> "That this House agrees with the Fourth Report of the Business Advisory Committee presented to the House on the 14th August, 1962."

Shri S. M. Banerjee (Kanpur): According to the Order Paper, we are going to take up a new motion at 3 p.m. The time allotted for the discussion on railway accidents is, I am told, five hours. So, I would like to know whether the discussion on that would continue for the whole day or will be postponed to some other day.

Mr. Speaker: He should raise it after we have adopted the motion.

The question is:

> "That this House agrees with the Fourth Report of the Business Advisory Committee presented to the House on the 14th August, 1962."

The motion was adopted.

Shri S. M. Banerjee: According to the Order Paper for today, we will now take up further consideration of the Eleventh Report of the UPSC. At 3 p.m. we are going to take up the Report of the Commissioner for Linguistic Minorities. I am told that five hours have been allotted for the discussion on railway accidents. Does it mean that it will be continued tomorrow or some other day?

Mr. Speaker: It will be continued and it will be given the full time allotted to it.

Shri Surendranath Dwivedy (Kendrapara): We have accepted the allotment of five hours for the discussion on railway accidents. Since we are at present discussing the report of the UPSC and as we have to take up the Report of the Commisioner for Linguistic Minorities at 3 p.m. there will be hardly one and a half hours for the discussion on railway accidents today. In this connection I may submit that the discussion of the Report of the Commissioner for Linguistic Minorities is on a motion by a private Member, notice for which was given during the last session. Since then, the third Report of the Commissioner has been laid on the Table. I suggest that we may take up the two reports for discussion together later on.

Mr. Speaker: Then Members may object that they did not get advance notice.

Shri S. M. Banerjee: Will the motion fixed for 3 P.M. come today or tomorrow?

Mr. Speaker: Since it is fixed for a particular period, we must take it up at that time. After that, we will take up the other discussion.

Shri S. M. Banerjee: After the discussion on railway accidents, according to the Order Paper, there are Supplementary Demands for Grants.

Mr. Speaker: They are not likely to come up today.

12.28 hrs.

MOTION RE: REPORT OF UNION PUBLIC SERVICE COMMISSION—*Contd.*

Mr. Speaker: The House will now take up further consideration of the motion moved by Shri Datar regarding the Eleventh Report of the Union Public Service Commission. Shri K. Pattnayak will continue his speech.

श्री कि० पटनायक (सम्बलपुर) अध्यक्ष महोदय, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन का निर्माण संविधान के द्वारा हुआ है और यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण संस्था है। लेकिन गये सालों में पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा ऐसा कुछ भी काम नहीं हुआ, जिससे कि इस देश के प्रशासन में कोई मौलिक परिवर्तन हो सके। जब ब्रिटिश ज़माना था, अंग्रेज़ों की सरकार थी, उस समय अफसर लोग जिस किस्म के थे और वे जिस ढंग से शासन चलाते थे अभी भी आज़ाद हिन्दूस्तान के अफसर वैसे ही हैं और उस ढंग से ही काम चलाते हैं। जनता के साथ उनका सम्पर्क भी अभी वैसे ही है, जैसे कि अंग्रेज़ के ज़माने में था। इसमें परिवर्तन लाना गृह मंत्रालय तथा पब्लिक सर्विस कमीशन दोनों की जिम्मेदारी होनी चाहिये थी। लेकिन इन दोनों के द्वारा अभी तक इस दिशा में कोई कदम नहीं उठाया गया है।

एक तो यह है कि संविधान का जो पार्ट १७ है आफिशल लैंगुएज के बारे में उसको कार्यान्वित करने की कुछ जिम्मेदारी इस पब्लिक सर्विस कमीशन तथा गृह मंत्रालय को होनी चाहिये थी। लेकिन उस दिशा में तो अभी तक कुछ भी नहीं हुआ है। संविधान की ३४३, ३४४ और ३४५ जो धारायें हैं, उनकी अवहेलना देश में जितने अधिकारी हैं सबके द्वारा हो रही है प्रधान मंत्री से लेकर असैम्बलियों और पार्लियामेंट के स्पीकर द्वारा हो रही है। सभी इन धाराओं को शायद भूल ही गए हैं और शायद उन सबको पता नहीं है कि संविधान में ऐसी भी कोई प्राविजन है कि पद्रह साल के बाद यह अंग्रेजी नहीं चलने वाली है और इसलिए देश को तैयार होना चाहिये, पार्लियामेंट में, असैम्बलियों में तथा दफ्तरों में ताकि उसके बाद दूसरी भाषा इसका स्थान ले। लेकिन इस अंग्रेजी के स्थान को बदलने के लिये अभी तक क्या हुआ है? अभी तक कुछ भी नहीं हुआ है और न ही इसके बारे में कोई चेष्टा ही की गई है और अब ऐसी चर्चा है कि एक संशोधन इसके बारे में पेश किया जाएगा। इस असफलता को छिपाने के लिये बार बार यह प्रश्न उठ रहा है कि संविधान को बदलना पड़ेगा और शायद गृह मंत्री इसके लिये एक संशोधन पेश करेंगे अगर ऐसा किया जाता है तो यह एक बहुत ही बुरी चीज होगी। जो जिम्मेदारी इनके ऊपर थी, उस जिम्मेदारी को वह नहीं निभा पाये हैं, उसको पूरा नहीं कर पाये हैं और अपनी उस अयोग्यता को छिपाने के लिये अगर वह संशोधन लाया जायेगा तो यह बहुत ही बुरी चीज होगी। इस सैशन में वह उसको लाने वाले थे लेकिन अभी तक नहीं लाए हैं और मेरा निवेदन यह है कि वह उसको कभी भी न लायें। यह एक खतरनाक कीज़ हैं कि १९४७ में आज़ाद होने के बाद से हम जितना आगे बढ़ रहे हैं, आज़ादी के मूल्य को हम उतना ही भूलते जा रहे हैं। अंग्रेजी का पहले जितना विरोध था यह विरोध अब मंत्रियों और अधिकारियों की तरफ से कम होता जा